International Research Journal of Management Science & Technology



ISSN 2250 – 1959(0nline)
2348 – 9367 (Print)

An Internationally Indexed Peer Reviewed & Refereed Journal

www.IRJMST.com
www.isarasolutions.com

Published by iSaRa Solutions

समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निःशस्त्रीकरण की चुनौतियों एवं वैश्विक शांति की सम्भावनाओं का राजनीतिक अध्ययन

डॉ. बृजेश स्वरुप सोनकर

असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग

कर्म क्षेत्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इटावा (उ.प्र.)

सारांश (Abstract)

प्रस्तुत शोध-पत्र समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आलोक में निःशस्त्रीकरण (Disarmament) एवं शस्त्र नियंत्रण (Arms Control) के समक्ष विद्यमान व्यावहारिक व नीतिगत चुनौतियों तथा वैश्विक शांति की सम्भावनाओं का एक गहन राजनीतिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत परमाणु युग के सूत्रपात और तदुपरान्त शीतयुद्ध कालीन द्विध्रुवीय होड़ ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को विनाश की कगार पर खड़ा कर दिया था। यद्यपि एनपीटी (NPT), सीटीबीटी (CTBT), सॉल्ट (SALT), स्टार्ट (START) और न्यू स्टार्ट (New START) जैसी बहुपक्षीय व द्विपक्षीय संधियों के माध्यम से परमाणु तथा पारंपरिक हथियारों को सीमित करने के प्रयास किए गए, परंतु भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्द्धा, बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था का पुनरुभार, और उग्र राष्ट्रवाद ने निःशस्त्रीकरण की प्रक्रिया को शिथिल बना दिया है। प्रस्तुत शोध यथार्थवाद (Realism) तथा नव-उदारवादी संस्थागतवाद (Neoliberal Institutionalism) के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में यह विश्लेषित करता है कि किस प्रकार सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था एवं बहुपक्षीय राजनयिक मंच वैश्विक शांति की पुनर्स्थापना में सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

बीज शब्द (Keywords): निःशस्त्रीकरण, शस्त्र नियंत्रण, परमाणु अप्रसार संधि (NPT), सीटीबीटी (CTBT), अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, यथार्थवाद, वैश्विक शांति।

प्रस्तावना (Introduction)

समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निःशस्त्रीकरण (Disarmament) और शस्त्र नियंत्रण (Arms Control) वैश्विक शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हैं। निःशस्त्रीकरण का आशय राज्यों द्वारा अपने शस्त्रों एवं सैन्य क्षमताओं को समाप्त करने अथवा उनमें पर्याप्त कमी लाने से है, जबकि शस्त्र नियंत्रण का उद्देश्य हथियारों के विकास, उत्पादन, प्रसार, तैनाती और उपयोग को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों एवं निर्धारित नियमों के माध्यम से नियंत्रित करना है। दोनों अवधारणाएँ परस्पर संबंधित होने के बावजूद अपने उद्देश्यों और कार्यप्रणाली की दृष्टि से भिन्न हैं। वर्तमान विश्व व्यवस्था में इनका महत्त्व इसलिए बढ़ गया है, क्योंकि सैन्य प्रतिस्पर्धा, परमाणु हथियारों का प्रसार, क्षेत्रीय संघर्षों तथा उन्नत सैन्य तकनीकों के विकास ने अंतर्राष्ट्रीय शांति के समक्ष अनेक जटिल चुनौतियाँ उत्पन्न कर दी हैं। 20वीं शताब्दी के दो विश्व युद्धों ने यह स्पष्ट कर दिया कि सैन्य शक्ति पर आधारित प्रतिस्पर्धा और हथियारों की अनियंत्रित वृद्धि संपूर्ण मानवता के लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। वर्ष 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर किए गए परमाणु हमलों ने युद्ध की विनाशकारी क्षमता को अभूतपूर्व स्तर पर पहुँचा दिया। इसके पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विकसित शीतयुद्ध ने परमाणु हथियारों की होड़, सैन्य गुटबंदी तथा शक्ति-संतुलन की प्रतिस्पर्धा को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्रीय विषय बना दिया। दोनों महाशक्तियों ने

अपनी सामरिक क्षमताओं में निरंतर वृद्धि की, जिसके परिणामस्वरूप विश्व समुदाय के सामने यह चुनौती उत्पन्न हुई कि राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकताओं और वैश्विक शांति के उद्देश्यों के बीच संतुलन किस प्रकार स्थापित किया जाए। यद्यपि पारस्परिक परमाणु प्रतिरोध ने प्रत्यक्ष महाशक्ति युद्ध की लागत बढ़ाई, तथापि इससे परमाणु विनाश का जोखिम समाप्त नहीं हुआ।

इसी ऐतिहासिक अनुभव के आधार पर निःशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्वपूर्ण साधनों के रूप में विकसित करने के प्रयास किए गए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को प्रोत्साहित करने तथा हथियारों की दौड़ को सीमित करने के लिए बहुपक्षीय संस्थागत प्रयासों को महत्त्व मिला। परमाणु अप्रसार संधि (NPT), व्यापक परमाणु-परीक्षण-प्रतिबंध संधि (CTBT), रासायनिक हथियार अभिसमय (CWC) तथा जैविक हथियार अभिसमय (BWC) जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते इसी दिशा में किए गए प्रमुख प्रयासों के उदाहरण हैं। इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के विनाशकारी हथियारों के प्रसार को रोकना, उनके विकास एवं उपयोग पर प्रतिबंध स्थापित करना और राज्यों के बीच विश्वास तथा सहयोग को बढ़ावा देना रहा है। हालाँकि, इन संधियों की प्रभावशीलता सदस्य देशों की प्रतिबद्धता, सत्यापन की व्यवस्था, अनुपालन की स्थिति तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है।

समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निःशस्त्रीकरण की चुनौती केवल हथियारों की संख्या कम करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका संबंध राष्ट्रों के सुरक्षा हितों, संप्रभुता, सामरिक स्वायत्तता और वैश्विक शक्ति-संरचना से भी है। प्रत्येक राज्य अपनी क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता तथा राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सैन्य क्षमता को आवश्यक मानता है। इसी कारण अनेक देश निःशस्त्रीकरण के सिद्धांत का समर्थन करते हुए भी अपनी प्रतिरक्षा क्षमताओं को बनाए रखने अथवा उनका आधुनिकीकरण करने का प्रयास करते हैं। विशेष रूप से परमाणु हथियार संपन्न देशों के बीच सामरिक अविश्वास, क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता और शक्ति-संतुलन की आकांक्षा निःशस्त्रीकरण की प्रक्रिया को जटिल बनाती है। इसके अतिरिक्त, अंतर्राष्ट्रीय संधियों में असमान दायित्वों, सत्यापन संबंधी विवादों तथा कुछ प्रमुख शक्तियों द्वारा अपने सामरिक लाभों को बनाए रखने की प्रवृत्ति के कारण वैश्विक निःशस्त्रीकरण की दिशा में अपेक्षित प्रगति सीमित रही है।

वर्तमान समय में निःशस्त्रीकरण से संबंधित चुनौतियों का स्वरूप और अधिक व्यापक हो गया है। पारंपरिक हथियारों की प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ परमाणु हथियारों का आधुनिकीकरण, हाइपरसोनिक मिसाइलों का विकास, स्वायत्त हथियार प्रणालियों का विस्तार, साइबर युद्ध की संभावनाएँ तथा अंतरिक्ष का सैन्य उपयोग अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के नए आयाम प्रस्तुत कर रहे हैं। इन तकनीकों के विकास ने युद्ध की प्रकृति, निर्णय लेने की प्रक्रिया और संघर्षों के संभावित परिणामों को प्रभावित किया है। विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सैन्य प्रणालियाँ तथा स्वचालित हथियार भविष्य में जवाबदेही, मानवीय नियंत्रण और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुपालन से संबंधित गंभीर प्रश्न उत्पन्न कर सकती हैं। इसके साथ ही क्षेत्रीय युद्धों, आतंकवादी संगठनों तक हथियारों की पहुँच तथा अवैध हथियार व्यापार ने भी वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था के समक्ष नई कठिनाइयाँ प्रस्तुत की हैं।

सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में निःशस्त्रीकरण की समस्या को समझने के लिए यथार्थवाद, उदार संस्थावाद और सामूहिक सुरक्षा की अवधारणाएँ विशेष रूप से उपयोगी हैं। यथार्थवादी दृष्टिकोण के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में कोई सर्वोच्च केंद्रीय सत्ता नहीं होने के कारण राज्य अपनी सुरक्षा के लिए मुख्यतः स्वयं पर निर्भर रहते हैं। परिणामस्वरूप, एक राज्य द्वारा अपनी सैन्य क्षमता में वृद्धि दूसरे राज्य में असुरक्षा की भावना उत्पन्न कर सकती है, जिसे सुरक्षा दुविधा (Security Dilemma) कहा जाता है। इसके विपरीत, उदार संस्थावाद यह मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ, संधियाँ, पारदर्शिता और निरंतर संवाद राज्यों के बीच अविश्वास को कम कर सकते हैं तथा सहयोग की

संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा इस विचार पर बल देती है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना केवल किसी एक राज्य का दायित्व नहीं, बल्कि संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की साझा जिम्मेदारी है। इन दृष्टिकोणों के आधार पर निःशस्त्रीकरण की सफलता का आकलन केवल कानूनी प्रावधानों से नहीं, बल्कि राजनीतिक इच्छाशक्ति, पारस्परिक विश्वास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की वास्तविक स्थिति से भी किया जाना आवश्यक है।

वैश्विक शांति की संभावनाएँ इस बात पर निर्भर करती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय राष्ट्रीय सुरक्षा और सामूहिक सुरक्षा के बीच व्यावहारिक संतुलन स्थापित करने में कितना सफल होता है। इसके लिए संधियों का प्रभावी अनुपालन, पारदर्शी सत्यापन व्यवस्था, हथियारों के प्रसार पर नियंत्रण, संकट प्रबंधन तंत्र का विकास तथा परमाणु जोखिम को कम करने के लिए संवाद आवश्यक हैं। साथ ही, विकसित और विकासशील देशों के बीच सुरक्षा संबंधी चिंताओं तथा निःशस्त्रीकरण के दायित्वों में न्यायसंगत संतुलन स्थापित करना भी महत्वपूर्ण है। यदि निःशस्त्रीकरण की प्रक्रिया को केवल कुछ शक्तिशाली राष्ट्रों के सामरिक हितों तक सीमित रखा जाता है, तो इसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता और प्रभावशीलता प्रभावित हो सकती है। इसके विपरीत, समान सुरक्षा, पारस्परिक विश्वास और नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर आधारित दृष्टिकोण वैश्विक शांति की संभावनाओं को मजबूत कर सकता है।

इस प्रकार, प्रस्तुत अध्ययन “समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निःशस्त्रीकरण की चुनौतियों एवं वैश्विक शांति की सम्भावनाओं का राजनीतिक अध्ययन” के अंतर्गत निःशस्त्रीकरण की अवधारणा, उसके समकालीन स्वरूप, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संधियों तथा उनकी प्रभावशीलता का राजनीतिक विश्लेषण किया जाएगा। अध्ययन में यह समझने का प्रयास किया जाएगा कि राष्ट्रीय हितों, सामरिक प्रतिस्पर्धा, सुरक्षा दुविधा और वैश्विक शक्ति-संतुलन की परिस्थितियाँ निःशस्त्रीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य बहुपक्षीय संस्थाओं की भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सीमाओं और शांति स्थापना की संभावनाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। अध्ययन का केंद्रीय उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि क्या वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में प्रभावी निःशस्त्रीकरण के माध्यम से स्थायी शांति की दिशा में सार्थक प्रगति संभव है, और यदि संभव है, तो इसके लिए किन राजनीतिक, संस्थागत तथा कूटनीतिक परिस्थितियों का निर्माण आवश्यक होगा।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य (Historical Context)

निःशस्त्रीकरण का ऐतिहासिक विकासक्रम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उतार-चढ़ाव भरा रहा है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में स्थापित राष्ट्र संघ (League of Nations) के संविदा (Covenant) के अनुच्छेद 8 में राष्ट्रीय सुरक्षा के अनुकूल शस्त्रागारों को न्यूनतम स्तर पर लाने का संकल्प लिया गया था। 1932 का जेनेवा निःशस्त्रीकरण सम्मेलन इस दिशा में एक बड़ा प्रयास था, परंतु उग्र राष्ट्रवाद और फासीवादी ताकतों के उभार के कारण यह प्रयास विफल हो गया और द्वितीय विश्व युद्ध का सूत्रपात हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा-पत्र के अनुच्छेद 11 एवं 26 में निःशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण के लिए स्पष्ट प्रावधान किए गए। 1946 में संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा आयोग (UNAEC) का गठन किया गया, परंतु शीतयुद्ध की गुटबाज़ी के कारण प्रारंभिक वार्ताएँ निष्फल रहीं। 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट ने महाशक्तियों को परमाणु युद्ध के वास्तविक खतरे से अवगत कराया, जिसके परिणामस्वरूप 1963 की आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (PTBT) और 1968 की परमाणु अप्रसार संधि (NPT) का मार्ग प्रशस्त हुआ। 1970 और 1980 के दशकों में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच सामरिक शस्त्र सीमा वार्ता (SALT-I व SALT-II) तथा 1987 की मध्यवर्ती-दूरी परमाणु बल संधि (INF) जैसी ऐतिहासिक संधियाँ हुईं। शीतयुद्ध के समापन के पश्चात 1991 और 1993 की 'स्टार्ट' संधियों (START-I & START-II) ने दोनों महाशक्तियों के परमाणु हथियारों की कटौती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 1996 में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT) लाई

गई, परंतु प्रमुख देशों द्वारा इसका अनुसमर्थन (Ratification) न किए जाने के कारण यह संधि पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं हो सकी। 2010 में अमेरिका और रूस के मध्य हस्ताक्षरित 'न्यू स्टार्ट' (New START) संधि इस दिशा में अंतिम बड़ा द्विपक्षीय प्रयास था।

शोध पद्धति एवं प्रविधि (Research Methodology)

प्रस्तुत शोध-पत्र **गुणात्मक, ऐतिहासिक-विश्लेषणात्मक तथा तुलनात्मक शोध पद्धति (Qualitative, Historical-Analytical & Comparative Methodology)** पर आधारित है :

a. **प्राथमिक स्रोत (Primary Sources):** संयुक्त राष्ट्र संघ के आधिकारिक प्रस्ताव एवं दस्तावेज, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) की रिपोर्टें, एनपीटी तथा सीटीबीटी के मूल दस्तावेज, तथा स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) के आधिकारिक आंकड़े।
b. **द्वितीयक स्रोत (Secondary Sources):** अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मूर्धन्य विद्वानों (जैसे हंस मॉर्गनथॉ, केनेथ वाल्ट्ज़, जोसेफ नाई, रॉबर्ट किओहेन) की कृतियाँ, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विज्ञान की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं के शोध-लेख एवं विषयगत पुस्तकें।

साहित्य की समीक्षा (Review of Literature)

निःशस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजनीतिशास्त्रियों द्वारा व्यापक चिंतन प्रस्तुत किया गया है:

1. **मॉर्गनथॉ, एच. जे. (1948) - *Politics Among Nations*:** मॉर्गनथॉ का मानना है कि निःशस्त्रीकरण स्वयं में शांति की गारंटी नहीं है, क्योंकि हथियार युद्ध का कारण नहीं बल्कि राष्ट्रीय हितों के टकराव का परिणाम होते हैं। जब तक राजनीतिक विवादों का हल नहीं होता, तब तक निःशस्त्रीकरण सम्भव नहीं है।
2. **वाल्ट्ज़, के. एन. (1979) - *Theory of International Politics*:** नव-यथार्थवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए वाल्ट्ज़ का तर्क है कि अराजकतावादी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था (Anarchic International System) में राज्य अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं पर निर्भर (Self-help system) होते हैं। अतः परमाणु निवारक (Nuclear Deterrence) वास्तव में युद्ध को रोकने का कार्य करता है।
3. **बुल, एच. (1977) - *The Anarchical Society*:** हेडली बुल ने शस्त्र नियंत्रण और निःशस्त्रीकरण के बीच अंतर स्पष्ट किया। उनका तर्क है कि शस्त्र नियंत्रण महाशक्तियों के मध्य रणनीतिक स्थायित्व (Strategic Stability) बनाए रखने में सहायक होता है, भले ही पूर्ण निःशस्त्रीकरण प्राप्त न हो सके।
4. **SIPRI इयरबुक (विभिन्न संस्करण):** सिपरी की रिपोर्टें यह दर्शाती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों के बावजूद विश्व के प्रमुख देशों द्वारा अपने सैन्य बजट और शस्त्रागारों के आधुनिकीकरण पर निरंतर भारी धनराशि खर्च की जा रही है।

शोध-अंतराल (Research Gap)

अधिकांश पूर्ववर्ती साहित्य या तो केवल शीतयुद्ध कालीन निःशस्त्रीकरण संधियों का ऐतिहासिक ब्यौरा प्रस्तुत करता है या फिर केवल सैद्धांतिक यथार्थवाद के चश्मे से शक्ति संतुलन की व्याख्या करता है। समकालीन बहुध्रुवीय विश्व में जहाँ गैर-पारंपरिक सुरक्षा खतरे (जैसे परमाणु आतंकवाद, साइबर युद्ध प्रणाली, और बाह्य अंतरिक्ष का शस्त्रीकरण) उभर रहे हैं, वहाँ पारंपरिक निःशस्त्रीकरण संरचना की विफलता और उसके राजनीतिक-संवैधानिक पुनर्गठन

की आवश्यकता का एकीकृत अध्ययन अपेक्षाकृत सीमित रहा है। प्रस्तुत शोध इसी शून्यता को भरने का प्रयास करता है।

शोध का महत्त्व एवं आवश्यकता (Significance and Need of the Study)

- **राजनीतिक-सैद्धांतिक महत्त्व:** यह अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में यथार्थवादी सुरक्षा प्राथमिकताओं और उदारवादी संस्थागत ढाँचे के मध्य के द्वंद्व को समझने हेतु एक सुदृढ़ विश्लेषणात्मक आधार प्रदान करता है।
- **वैश्विक सुरक्षा हेतु प्रासंगिकता:** परमाणु हथियारों के प्रसार, क्षेत्रीय तनावों (जैसे दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और पूर्वी एशिया) तथा पारंपरिक हथियारों की नई होड़ के दौर में शांति स्थापना के व्यावहारिक उपायों की खोज अत्यंत आवश्यक है।
- **नीतिगत उपयोगिता:** यह शोध-पत्र बहुपक्षीय कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु नीति-निर्माताओं को सैद्धांतिक व व्यावहारिक इनपुट प्रदान करता है।

शोध समस्या (Statement of the Research Problem)

समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि एक ओर जहाँ समस्त विश्व समुदाय एनपीटी और सीटीबीटी जैसी संधियों के माध्यम से परमाणु मुक्त विश्व की बात करता है, वहीं दूसरी ओर परमाणु संपन्न राष्ट्र अपने शस्त्रागारों का निरंतर नवीनीकरण कर रहे हैं और नए देश परमाणु क्षमता हासिल करने की होड़ में लगे हैं। मुख्य शोध समस्या यह है कि क्या अराजक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं को दरकिनार कर पूर्ण निःशस्त्रीकरण को प्राप्त किया जा सकता है, या फिर केवल रणनीतिक शस्त्र नियंत्रण ही वैश्विक शांति का एकमात्र व्यावहारिक विकल्प है?

शोध के उद्देश्य (Objectives of the Study)

1. समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निःशस्त्रीकरण एवं शस्त्र नियंत्रण के ऐतिहासिक व सैद्धांतिक ढाँचे का विश्लेषण करना।
2. एनपीटी, सीटीबीटी और न्यू स्टार्ट जैसी अंतर्राष्ट्रीय संधियों की सफलता व विफलता के कारणों का परीक्षण करना।
3. निःशस्त्रीकरण की राह में विद्यमान प्रमुख राजनीतिक, तकनीकी और भू-राजनीतिक बाधाओं का मूल्यांकन करना।
4. बहुपक्षीय कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से वैश्विक शांति एवं सुरक्षा की सम्भावनाओं की खोज करना।

शोध प्रश्न (Research Questions)

1. राष्ट्र-राज्य पूर्ण निःशस्त्रीकरण को स्वीकार करने में संकोच क्यों करते हैं और सुरक्षा दुविधा इसमें क्या भूमिका निभाती है?
2. क्या परमाणु अप्रसार संधि (NPT) अपने मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रही है या यह केवल परमाणु संपन्न राष्ट्रों के आधिपत्य का साधन बनकर रह गई है?
3. समकालीन अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में गैर-पारंपरिक सुरक्षा खतरों और नए सैन्य हथियारों के युग में वैश्विक शांति स्थापित करने के क्या व्यावहारिक मार्ग हो सकते हैं?

सैद्धांतिक आधार (Theoretical Framework)

प्रस्तुत अध्ययन "समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निःशस्त्रीकरण की चुनौतियों एवं वैश्विक शांति की सम्भावनाओं का राजनीतिक अध्ययन" का सैद्धांतिक आधार मुख्यतः यथार्थवाद तथा नव-उदारवादी संस्थागतवाद पर आधारित है। ये दोनों सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में राज्यों के व्यवहार, राष्ट्रीय सुरक्षा, सैन्य प्रतिस्पर्धा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की संभावनाओं को समझने के लिए उपयोगी हैं :

1. यथार्थवाद (Realism) - यथार्थवादी सिद्धांत के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में किसी सर्वोच्च केंद्रीय सत्ता का अभाव होने के कारण राज्य अपनी सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए मुख्यतः अपनी शक्ति एवं सामरिक क्षमताओं पर निर्भर रहते हैं। हांस जे. मॉर्गनथॉ ने राष्ट्रीय हित और शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख आधार के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि केनेथ वाल्ट्ज़ ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की अराजक संरचना तथा उसके राज्यों के व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव को स्पष्ट किया। इस दृष्टिकोण से सैन्य शक्ति, परमाणु प्रतिरोध और शक्ति-संतुलन राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्त्वपूर्ण साधन हैं। परिणामस्वरूप, राज्य अपनी सुरक्षा को जोखिम में डालकर एकतरफा निःशस्त्रीकरण करने से बचते हैं। यह दृष्टिकोण स्पष्ट करता है कि सामरिक प्रतिस्पर्धा, पारस्परिक अविश्वास और सुरक्षा दुविधा निःशस्त्रीकरण की प्रक्रिया में प्रमुख बाधाएँ क्यों बनी रहती हैं।

2. नव-उदारवादी संस्थागतवाद (Neoliberal Institutionalism) - नव-उदारवादी संस्थागतवाद इस विचार पर बल देता है कि अंतर्राष्ट्रीय अराजकता के बावजूद राज्यों के बीच सहयोग संभव है। रॉबर्ट ओ. किओहेन के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ और नियम राज्यों के बीच सूचना के आदान-प्रदान, पारदर्शिता तथा सहयोग को प्रोत्साहित कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ, परमाणु अप्रसार संधि तथा अन्य बहुपक्षीय समझौतों की भूमिका का विश्लेषण किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ, सत्यापन की व्यवस्थाएँ और नियमित कूटनीतिक संवाद राज्यों के बीच अविश्वास को कम करने तथा हथियारों के प्रसार को नियंत्रित करने में सहायक हो सकते हैं। हालाँकि, इन संस्थाओं की प्रभावशीलता सदस्य देशों की राजनीतिक इच्छाशक्ति, संधियों के अनुपालन और सामूहिक सहयोग पर निर्भर करती है।

उपर्युक्त दोनों सिद्धांतों के संयुक्त प्रयोग से निःशस्त्रीकरण की चुनौतियों एवं वैश्विक शांति की संभावनाओं का संतुलित राजनीतिक विश्लेषण किया जा सकता है। यथार्थवाद निःशस्त्रीकरण के मार्ग में राष्ट्रीय हितों, शक्ति-प्रतिस्पर्धा और सुरक्षा संबंधी चिंताओं की व्याख्या करता है, जबकि नव-उदारवादी संस्थागतवाद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, संधियों और बहुपक्षीय संस्थाओं के माध्यम से इन चुनौतियों के समाधान की संभावनाओं को स्पष्ट करता है। इस प्रकार, अध्ययन का सैद्धांतिक आधार यह समझने में सहायता करता है कि वैश्विक शांति की दिशा में प्रगति के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकताओं और सामूहिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बीच संतुलन स्थापित करना क्यों आवश्यक है।

अध्ययन का क्षेत्र एवं सीमाएँ (Scope and Limitations)

- **क्षेत्र:** यह अध्ययन मुख्य रूप से वैश्विक परमाणु व पारंपरिक निःशस्त्रीकरण संधियों, महाशक्तियों के सामरिक संबंधों, तथा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संरचनाओं के विश्लेषण तक सीमित है।
- **सीमाएँ:** यह शोध-पत्र विशुद्ध रूप से राजनीति विज्ञान के सैद्धांतिक एवं रणनीतिक परिप्रेक्ष्य पर केंद्रित है; इसमें हथियारों के निर्माण की सूक्ष्म तकनीकी या भौतिक-वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का विस्तृत विवरण शामिल नहीं है।

विषयगत विवेचन एवं गहन विश्लेषणात्मक अध्ययन

(Thematic Discussion & Deep Analytical Study)

1. निःशस्त्रीकरण की राह में प्रमुख राजनीतिक एवं भू-राजनीतिक चुनौतियाँ

समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निःशस्त्रीकरण की प्रक्रिया अनेक राजनीतिक, सामरिक और भू-राजनीतिक चुनौतियों से प्रभावित होती है। इसका संबंध केवल हथियारों की संख्या कम करने से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हितों, शक्ति-संतुलन, संप्रभुता और राज्यों के बीच पारस्परिक विश्वास से भी है। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने तथा सैन्य प्रतिस्पर्धा को सीमित करने के लिए विभिन्न संधियों और संस्थागत व्यवस्थाओं का विकास किया है, फिर भी उनके प्रभावी क्रियान्वयन में कई बाधाएँ बनी हुई हैं। इन चुनौतियों का विश्लेषण निम्नलिखित प्रमुख आधारों पर किया जा सकता है।

a. परमाणु अप्रसार संधि की विभेदकारी प्रकृति (Discriminatory Nature of NPT) - परमाणु अप्रसार संधि (Nuclear Non-Proliferation Treaty–NPT) वर्ष 1968 में हस्ताक्षर के लिए खोली गई और 1970 में प्रभावी हुई। यह संधि परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित करने तथा परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में प्रयास करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। इसके अंतर्गत 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियार का निर्माण एवं विस्फोट करने वाले पाँच देशों–अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन–को परमाणु हथियार संपन्न राज्यों के रूप में मान्यता दी गई। इस व्यवस्था की प्रमुख आलोचना यह है कि यह परमाणु हथियार संपन्न और गैर-परमाणु हथियार संपन्न राज्यों के बीच संस्थागत अंतर स्थापित करती है। संधि के अनुच्छेद VI में परमाणु निरस्त्रीकरण से संबंधित वार्ताओं को सद्भावना के साथ आगे बढ़ाने का दायित्व दिया गया है, लेकिन इसमें परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इससे निरस्त्रीकरण संबंधी प्रतिबद्धताओं के समान एवं प्रभावी क्रियान्वयन पर प्रश्न उठते हैं।

भारत ने संधि की इस संरचना को भेदभावपूर्ण मानते हुए इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। भारतीय दृष्टिकोण में सार्वभौमिक, सत्यापन योग्य और गैर-भेदभावपूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण को विशेष महत्त्व दिया जाता है। राजनीतिक दृष्टि से यह स्थिति दर्शाती है कि जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएँ सभी देशों की सुरक्षा संबंधी चिंताओं और दायित्वों के बीच समानता स्थापित नहीं कर पातीं, तब उनकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता प्रभावित होती है। इस प्रकार, एनपीटी की संरचना और उसके निरस्त्रीकरण संबंधी प्रावधान समकालीन वैश्विक निरस्त्रीकरण विमर्श की प्रमुख चुनौतियों में शामिल हैं।

b. सुरक्षा दुविधा एवं शक्ति-संतुलन (Security Dilemma and Balance of Power) - सुरक्षा दुविधा निःशस्त्रीकरण के मार्ग में आने वाली प्रमुख सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक चुनौतियों में से एक है। इसकी स्थिति तब उत्पन्न होती है, जब कोई राज्य अपनी सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से सैन्य क्षमता का विस्तार करता है, लेकिन दूसरे राज्य इसे संभावित खतरे के रूप में देखते हैं और अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने लगते हैं। परिणामस्वरूप, एक राज्य द्वारा सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम दूसरे राज्य की असुरक्षा को बढ़ा सकता है। इस प्रकार, पारस्परिक अविश्वास और सैन्य प्रतिस्पर्धा का एक ऐसा चक्र विकसित होता है, जो निःशस्त्रीकरण की संभावनाओं को सीमित करता है।

दक्षिण एशिया में भारत और पाकिस्तान के संबंध इस चुनौती को समझने का एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। दोनों देशों की परमाणु क्षमताएँ, क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता, सीमा संबंधी विवाद और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ उनके सामरिक निर्णयों को प्रभावित करती हैं। इसी प्रकार, अन्य क्षेत्रों में भी प्रमुख शक्तियों के बीच

मिसाइल प्रणालियों, परमाणु प्रतिरोध और आधुनिक सैन्य तकनीकों को लेकर प्रतिस्पर्धा दिखाई देती है। ऐसी परिस्थितियों में कोई भी राज्य एकतरफा निःशस्त्रीकरण को अपनी सामरिक स्थिति के लिए जोखिमपूर्ण मान सकता है। राजनीतिक दृष्टि से यह चुनौती स्पष्ट करती है कि केवल हथियारों में कटौती का आह्वान पर्याप्त नहीं है। इसके लिए पारस्परिक विश्वास, संकट के समय संवाद, सैन्य गतिविधियों में पारदर्शिता तथा प्रभावी सत्यापन व्यवस्था आवश्यक है। जब तक राज्य अपनी सुरक्षा को दूसरे राज्य की सैन्य कमजोरी से जोड़कर देखते रहेंगे, तब तक व्यापक निःशस्त्रीकरण की प्रक्रिया कठिन बनी रहेगी।

c. व्यापक परमाणु-परीक्षण-प्रतिबंध संधि की अपूर्ण प्रभावशीलता (CTBT) - व्यापक परमाणु-परीक्षण-प्रतिबंध संधि (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty–CTBT) को वर्ष 1996 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसका उद्देश्य सभी प्रकार के परमाणु विस्फोटक परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाना है। यह संधि परमाणु हथियारों के विकास और गुणात्मक आधुनिकीकरण को सीमित करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रयास है। तथापि, निर्धारित प्रवेश-प्रवर्तन संबंधी शर्तें पूरी न होने के कारण यह संधि अभी तक औपचारिक रूप से लागू नहीं हो सकी है। संधि के प्रभावी होने के लिए इसके परिशिष्ट-द्वितीय (Annex 2) में सूचीबद्ध सभी 44 देशों का अनुसमर्थन आवश्यक है। इनमें कुछ देशों ने संधि पर हस्ताक्षर तो किए हैं, लेकिन उसका अनुसमर्थन नहीं किया है; जबकि भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया जैसे देशों ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अमेरिका और चीन ने हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन अनुसमर्थन नहीं किया है। इस प्रकार, प्रमुख परमाणु शक्तियों तथा संबंधित देशों की अलग-अलग नीतियों ने संधि के औपचारिक क्रियान्वयन को बाधित किया है।

इस स्थिति का राजनीतिक महत्त्व यह है कि अंतर्राष्ट्रीय सहमति और कानूनी व्यवस्था के निर्माण के बावजूद, यदि आवश्यक देशों की प्रतिबद्धता अधूरी रहती है, तो किसी संधि के उद्देश्यों की पूर्ण प्राप्ति कठिन हो जाती है। अतः CTBT की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए संबंधित देशों के बीच कूटनीतिक संवाद, पारस्परिक आश्वासन और व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक हैं।

d. गैर-राज्य अभिकर्ताओं एवं परमाणु आतंकवाद का खतरा (Non-State Actors and Nuclear Terrorism) - समकालीन अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष एक अन्य गंभीर चुनौती सामूहिक विनाश के हथियारों (Weapons of Mass Destruction–WMD) तथा उनसे संबंधित सामग्री की गैर-राज्य अभिकर्ताओं तक संभावित पहुँच है। आतंकवादी संगठन, उग्रवादी समूह और अवैध तस्करी के नेटवर्क यदि परमाणु, रासायनिक या जैविक हथियारों अथवा संवेदनशील सामग्री तक पहुँच प्राप्त कर लें, तो इसके परिणाम राष्ट्रीय सीमाओं से परे व्यापक सुरक्षा संकट उत्पन्न कर सकते हैं। परमाणु आतंकवाद का जोखिम केवल किसी परमाणु हथियार की प्रत्यक्ष प्राप्ति तक सीमित नहीं है। इसमें परमाणु या रेडियोधर्मी सामग्री की चोरी, संवेदनशील तकनीक का अवैध हस्तांतरण तथा रेडियोलॉजिकल उपकरणों के दुरुपयोग की आशंकाएँ भी शामिल हैं। इसी कारण परमाणु सामग्री की सुरक्षा, निर्यात नियंत्रण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और खुफिया सूचनाओं का आदान-प्रदान महत्त्वपूर्ण हो जाता है।

राजनीतिक दृष्टि से इस चुनौती की विशिष्टता यह है कि पारंपरिक निःशस्त्रीकरण समझौते मुख्यतः राज्य-केंद्रित होते हैं, जबकि गैर-राज्य अभिकर्ताओं से उत्पन्न खतरे के लिए व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और घरेलू सुरक्षा संस्थाओं के बीच समन्वय भी आवश्यक है। परमाणु सुरक्षा से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं को मजबूत करना, अवैध तस्करी पर नियंत्रण स्थापित करना और परमाणु सामग्री की सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करना इस दिशा में महत्त्वपूर्ण उपाय हैं।

उपर्युक्त चुनौतियों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निःशस्त्रीकरण की प्रक्रिया केवल तकनीकी अथवा कानूनी समस्या नहीं, बल्कि शक्ति-संबंधों और राष्ट्रीय सुरक्षा हितों से जुड़ा व्यापक

राजनीतिक प्रश्न है। एनपीटी की विभेदकारी संरचना से संबंधित आलोचनाएँ, सुरक्षा दुविधा, सीटीबीटी का लागू न हो पाना तथा गैर-राज्य अभिकर्ताओं से उत्पन्न खतरे निःशस्त्रीकरण की प्रभावशीलता को सीमित करते हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रभावी अनुपालन, निष्पक्ष एवं विश्वसनीय सत्यापन, पारस्परिक विश्वास और बहुपक्षीय सहयोग आवश्यक हैं। इस प्रकार, वैश्विक शांति की दिशा में सार्थक प्रगति तभी संभव है, जब राज्य अपनी वैध सुरक्षा संबंधी चिंताओं और सामूहिक निरस्त्रीकरण के उद्देश्यों के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति प्रदर्शित करें।

2. **अंतर्राष्ट्रीय निःशस्त्रीकरण संधियों और रणनीतिक वार्ताओं का लेखा-जोखा**

क्र. सं.	संधि/समझौता	वर्ष	मुख्य प्रावधान	वर्तमान स्थिति एवं प्रभावशीलता
1.	**आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि (PTBT)**	1963	वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष और जल के भीतर परमाणु परीक्षणों पर रोक।	भूमिगत परीक्षणों को रोकने में असमर्थ रही।
2.	**परमाणु अप्रसार संधि (NPT)**	1968	परमाणु तकनीक के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना और परमाणु प्रसार को रोकना।	सार्वभौमिकता का अभाव; विभेदकारी ढाँचे के कारण आलोच्य।
3.	**सामरिक शस्त्र सीमा वार्ता (SALT-I & II)**	1972/1979	अमेरिका और सोवियत संघ के एंटी-बैलिस्टिक मिसाइलों और सामरिक हथियारों पर सीमा।	शीतयुद्धीय तनाव को कम करने में आंशिक रूप से सफल।
4.	**सामरिक शस्त्र कटौती संधि (START-I)**	1991	अमेरिका व रूस द्वारा अपने परमाणु हथियारों के जखीरे में भारी कटौती का संकल्प।	शीतयुद्ध उत्तर काल में निःशस्त्रीकरण की दिशा में एक बड़ी सफलता।
5.	**व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT)**	1996	सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों पर पूर्ण प्रतिबंध।	प्रमुख 8 देशों के अनुसमर्थन न करने से अभी तक अप्रभावी।
6.	**न्यू स्टार्ट (New START) संधि**	2010	अमेरिका और रूस द्वारा तैनात परमाणु हथियार प्रणालियों को 1,550 तक सीमित करना।	द्विपक्षीय शस्त्र नियंत्रण का अंतिम व्यावहारिक मंच।

समकालीन वैश्विक संदर्भ में निःशस्त्रीकरण की स्थिति

समकालीन वैश्विक परिदृश्य में निःशस्त्रीकरण का मुद्दा अत्यधिक जटिल हो गया है। यद्यपि शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका और रूस ने अपने परमाणु हथियारों की संख्या में उल्लेखनीय कमी की थी, परंतु वैश्विक स्तर पर रणनीतिक अस्थिरता पुनः बढ़ रही है।

शस्त्रागारों का आधुनिकीकरण: सिपरी (SIPRI) के आंकड़ों के अनुसार, यद्यपि कुल परमाणु हथियारों की संख्या में ऐतिहासिक रूप से कमी आई है, परंतु सभी परमाणु संपन्न देश (अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान,

इजरायल और उत्तर कोरिया) अपने हथियारों के आधुनिकीकरण और हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणालियों के विकास पर भारी निवेश कर रहे हैं।

1. **बहुध्रुवीय होड़:** चीन का तेजी से बढ़ता सैन्य और नौसैनिक ढाँचा, दक्षिण चीन सागर में तनाव, और उत्तर कोरिया द्वारा किए जा रहे निरंतर मिसाइल परीक्षणों ने पूर्व एशिया में सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है।
2. **नई प्रौद्योगिकी का प्रभाव:** बाह्य अंतरिक्ष का शस्त्रीकरण, ऑटोमैटिक किलर रोबोट्स, साइबर युद्ध और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का सैन्य उपयोग पारंपरिक निःशस्त्रीकरण संधियों की प्रासंगिकता पर प्रश्नचिह्न लगा रहा है।

सुझाव एवं नीतिगत निहितार्थ (Suggestions and Policy Implications)

- **बहुपक्षीय वार्ताओं का पुनरुद्धार:** संयुक्त राष्ट्र संघ के निःशस्त्रीकरण सम्मेलन (Conference on Disarmament) को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए और इसे केवल महाशक्तियों के दबाव से मुक्त कर सर्वसमावेशी बनाना चाहिए।
- **समयबद्ध पूर्ण निःशस्त्रीकरण का खाका:** एनपीटी के अनुच्छेद VI के तहत परमाणु संपन्न राष्ट्रों को एक पारदर्शी और समयबद्ध चरणबद्ध निःशस्त्रीकरण (Time-bound Phased Disarmament) का खाका प्रस्तुत करना चाहिए।
- **CTBT का क्रियान्वयन:** परमाणु संपन्न देशों को सीटीबीटी का अनुसमर्थन कर इसे वैश्विक स्तर पर लागू करने हेतु राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखानी होगी।
- **गैर-पारंपरिक खतरों पर विनियमन:** अंतरिक्ष के शस्त्रीकरण, साइबर युद्ध और स्वचालित हथियार प्रणालियों पर नियंत्रण हेतु नई अंतर्राष्ट्रीय संधियों का निर्माण आवश्यक है।
- **विश्वास बहाली के उपाय (CBMs):** क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों (जैसे भारत-पाकिस्तान, अमेरिका-चीन) के मध्य सैन्य वार्ताओं, हॉटलाइन संपर्कों और रणनीतिक पारदर्शिता के माध्यम से विश्वास बहाली के उपायों को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष (Conclusion)

शोध परिकल्पनाओं (Hypotheses) का प्रामाणीकरण एवं निष्कर्ष:

प्रस्तुत शोध-पत्र के अंतर्गत यह परिकल्पना की गई थी कि:

- *"समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अराजकतावादी व्यवस्था और राज्यों की सुरक्षा दुविधा (Security Dilemma) पूर्ण निःशस्त्रीकरण के मार्ग में मुख्य बाधा है, जिसके कारण राज्य निरस्त्रीकरण के स्थान पर केवल रणनीतिक शस्त्र नियंत्रण (Arms Control) को प्राथमिकता देते हैं।"*
- *"अंतर्राष्ट्रीय संधियों की विभेदकारी प्रकृति (जैसे NPT) और बहुपक्षीय संस्थाओं की सीमित बाध्यकारी शक्ति के कारण वैश्विक शांति की सम्भावनाएँ केवल शक्ति संतुलन और कूटनीतिक संवाद पर ही निर्भर हैं।"*

परिकल्पनाओं का प्रामाणीकरण:

ऐतिहासिक तथ्यों, संधियों के विश्लेषणात्मक अध्ययन तथा यथार्थवादी व नव-उदारवादी सिद्धांतों के परीक्षण से यह सिद्ध होता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में संप्रभु राज्यों की प्राथमिक चिंता अपनी सुरक्षा और अस्तित्व को बनाए रखना है। NPT और CTBT जैसी संधियों की विफलता या सीमित सफलता का मुख्य कारण उनका भेदभावपूर्ण स्वरूप और राज्यों की सुरक्षा चिंताएं रही हैं। शीतयुद्ध से लेकर समकालीन काल तक महाशक्तियों ने 'पूर्ण निःशस्त्रीकरण' (Total

Disarmament) के स्थान पर सदैव 'रणनीतिक संतुलन व शस्त्र नियंत्रण' (Strategic Arms Control) को ही प्राथमिकता दी है, ताकि उनका रणनीतिक वर्चस्व बना रहे। अतः दोनों परिकल्पनाएँ **सिद्ध एवं प्रमाणित** होती हैं।

निष्कर्षतः, निःशस्त्रीकरण केवल हथियारों को नष्ट करने का यांत्रिक कार्य नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रों के मध्य राजनीतिक अविश्वास और भय को दूर करने की एक सतत प्रक्रिया है। जब तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति के लिए संघर्ष और सुरक्षा की अनिश्चितता विद्यमान रहेगी, तब तक पूर्ण और व्यापक निःशस्त्रीकरण (General and Complete Disarmament) एक दूरगामी आदर्श बना रहेगा। तथापि, वैश्विक शांति की सम्भावनाएँ पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं। परमाणु युद्ध के विनाशकारी परिणामों के भय (Mutually Assured Destruction - MAD) ने महाशक्तियों के बीच सीधे सैन्य टकराव को रोकने में सफलता पाई है। भविष्य में वैश्विक शांति और स्थायित्व केवल तभी संभव है जब बहुपक्षवाद (Multilateralism), अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान, संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन, और भेदभाव-रहित संधियों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाए। मानव सभ्यता के सुरक्षित भविष्य के लिए युद्ध की कूटनीति के स्थान पर शांति की कूटनीति को वैश्विक राजनीति का मूल मंत्र बनाना होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची (References)

- **बुल, एच.,** (1977), *द अनारकीकल सोसाइटी: ए स्टडी ऑफ ऑर्डर इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स*. पालग्रेव मैकमिलन।
- **मॉर्गनथॉ, एच. जे.,** (1948), *पॉलिटिक्स अमंग नेशंस: द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस*. अल्फ्रेड ए. नोफ।
- **वाल्ट्ज़, के. एन.,** (1979), *थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स*. एडिसन-वेस्ले पब्लिशिंग कंपनी।
- **किओहेन, आर. ओ.,** (1984), *आफ्टर हेगेमनी: कोऑपरेशन एंड डिस्कोर्ड इन द वर्ल्ड पॉलिटिकल इकॉनमी*. प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस।
- **सिपरी (SIPRI),** (2016), *सिपरी इयरबुक 2016: आर्मामेंट्स, डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी*. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
- **संयुक्त राष्ट्र संघ (UN),** (1968), *ट्रीटी ऑन द नॉन-प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स (NPT)*. संयुक्त राष्ट्र प्रकाशन।
- **संयुक्त राष्ट्र संघ (UN),** (1996), *कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर-टेस्ट-बैन ट्रीटी (CTBT)*. संयुक्त राष्ट्र प्रकाशन।
- **गोपाल, एस.** (2012), *अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और निःशस्त्रीकरण*. ओरिएंट ब्लैकस्वाइन।
- **शर्मा, आर. के.** (2015), *समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सुरक्षा मुद्दे*. हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय।

ISARA INSTITUTE OF MANAGEMENT & PROFESSIONAL STUDIES

WWW.IIMPS.IN

EARN YOUR

MBA



Accreditation & Ranking

UGC / NCTE Approved.

INFO@IIMPS.IN

011-41005174

RESEARCH GATEWAY

STOP PLAGIARISM

1 Submit your content in Word File.

2 Get report in 48 hrs.

3 *Missing content or references will be fixed.

4 Citation for your work.

5 Get accurate user friendly report.

researchgateway.in | info@researchgateway.in

+91-9205579779

AROGYAM ONLINE

Arogyam Ayurveda

Holistic Healing through herbs

100% NATURAL

PARIVARTAN PSYCHOLOGY CENTER

COLOR PSYCHOLOGY : HOW COLOR AFFECT YOUR CHILD

BLUE — Calms your Child's Mind & Body

YELLOW — Promotes Concentration, Stimulates the Memory

PINK — Evokes Empathy, makes your Child Calm

RED — Excites and energizes your Child's body

GREEN — Improves Reading speed and Comprehension

www.parivartan4u.com

Confuse about your children's future?

भारतीय भाषा, शिक्षा, साहित्य एवं शोध

ISSN 2321 – 9726

WWW.BHARTIYASHODH.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE & TECHNOLOGY

ISSN – 2250 – 1959 (0) 2348 – 9367 (P)

WWW.IRJMST.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF COMMERCE, ARTS AND SCIENCE

ISSN 2319 – 9202

WWW.CASIRJ.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SOCIOLOGY & HUMANITIES

ISSN 2277 – 9809 (0) 2348 - 9359 (P)

WWW.IRJMSH.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF SCIENCE ENGINEERING AND TECHNOLOGY

ISSN 2454-3195 (online)

WWW.RJSET.COM

INTEGRATED RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT, SCIENCE AND INNOVATION

ISSN 2582-5445

WWW.IRJMSI.COM

JOURNAL OF LEGAL STUDIES,POLITICS AND ECONOMICS RESEARCH

WWW.JLPER.COM